tion system, that it would be difficult to evolve a proper system of distribution control.

SHRI K. GOPAL: On the one hand, the Minister says that there is no need to import paper and, on the other hand, she also admits that there is need for streamlining the distribution system. I would like to know what is the total demand of white paper in the country, what is the installed capacity and what actually is the production.

SHRIMATI ABHA MAITI: We need, at the moment, for educational sector, 2 lakh tonnes of white paper for printing text-books and also for exercise books. We need some paper for Government which is through the DGS&D. The total quantity is 2 lakh tonnes out of which 80,000 tonnes is for DGS&D and the remaining 1,20,000 tonnes for educational sector.

As regards the installed capacity, previously, the paper mills used to produce as they liked. Now, we have asked them that those who have got the capacity of 25 tonnes per day or more are required to manufacture 30 per cent of the total production in the form of white printing paper.

खादी ग्रामोद्योग में अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनाने के लिए सहायता की मांग

-I-

*952. **श्री रामसेवक हजारी :**
श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग पांच लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है और उसने इस उद्देश्य के लिए सरकार से 75 करोड़ रुपए की राशि की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का आयोग को कितनी सहायता देने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). The Khadi and Village Industries Commission is playing a predominent role in providing gainful employment opportunities on a substantial scale in the rural areas. Within its limited resources, the Government provides funds to the Khadi & Village Industries Commission as far as feasible. During the current year (1978-79) an allocation of Rs. 65.73 crores has been made to the Commission. It is expected that employment in the Khadi & Village Industries sector will increase from 25.60 lakhs in 1977-78 to 28.41 lakhs in 1978-79.

श्रीराम सेवक हजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि उद्योग मंत्रालय ने सरकार से 75 करोड़ रुपये की मांग की थी और सरकार की ओर से उद्योग मंत्रालय को 65 करोड़ 73 लाख रुपये का आवंटन किया गया है और 25.60 लाख लोगों को 1977-78 में रोजगार दिया गया और 1978-79 में 28.41 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार की योजना है । आप ने सरकार से 75 करोड़ रुपये की जो मांग की थी उस में से लगभग पौने दस करोड़ रुपयेकी कमी है मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यदि आप को पूरा रुपया मिल जाता तो जो आप ने 28.41 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, उस पूरी राशि मिल जाने पर आप कितने लोगों को रोजगार दे सकती हैं ? आज जो स्थिति बेरोजगारी की देश में है, उस को ध्यान में रखते हुए जो उद्योग मंत्रालय के लिए सरकार ने कटौती की है, वह मुनासिब नहीं है । इस साल जो 28.41 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है और पिछले साल जो 25.60 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, क्या इस सम्बन्ध में वे पूर्ण विवरण इस सदन को देंगी ?

SHRIMATI ABHA MAITI: In regard to the amount allotted to Khadi and Village Industries Commission, I may assure the Member that there will be no dearth of money for Khadi and Village Industries Commission, if they expand their work.

श्री राम सेवक हजारी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप ये केन्द्र खोलने जा रहे हैं, उनके लिए क्या आपका यह ध्यान रहेगा कि पिछड़े राज्यों में ये एक योजनाबद्ध ढ़ंग से और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार काम करना प्रारंभ कर दें ?

SHRIMATI ABHA MAITI: As the hon. Member knows, the Khadi and Village Industries Commission works through State Khadi and Village Industries Board. So, we would appreciate if the Member in his own State tries to enthuse the State Board to work on this. Then there will be no difficulty to work in the backward areas.

SHRI HITENDRA DESAI: How much additional employment was generated last year and what was the average daily earnings?

SHRIMATI ABHA MAITI: Last year, in 1977-78, it was Rs. 25.60 lakhs. As the hon. Member knows, this is a part-time work and the people used to work under the Khadi and Village Industries Commission. Generally, they used to get Rs. 3—8 per day.

SHRI HITENDRA DESAI: Is the Minister referring to additional employment?

SHRIMATI ABHA MAITI: The exact figure is not, at the present moment, available?

SHRI V. ARUNACHALAM: Whether the Government is aware of the fact that a number of societies started by the Khadi and Village Industries Commission are not functioning successfully. The entire amount of the loan was swallowed by the societies people before introducing new schemes. Will this Government assess the performance of the societies which are under the control of the Khadi Board?

SHRIMATI ABHA MAITI: The Khadi Board is under the control of the State Government. If there are such organisations which are not doing well, then the State Government can take care of them.

हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्ड में एकरूपता

*953. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टाइपराइटरों के "की-बोर्डों" में एकरूपता के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है;

(ख) आरम्भ से अब तक इस की बोर्ड में कितनी बार परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) क्या की-बोर्डों में बार-बार परिवर्तन करने से टाइपिस्टों को असुविधा होती है और उनकी गति बढ़ने में बाधा पड़ती है; और

(घ) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि की-बोर्डों का मानकीकरण न होने से निर्माता कम्पनियां हिन्दी टाइपराइटर नहीं बना रही हैं और उन्हें खरीदने के इच्छुक लोगों को दो-दो महीने बाद भी उनकी सप्लाई नहीं मिलती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ). देव नागरी टाइपराइटरों के कुंजी पटल को एक सुधरा